[Shri Mostafa Bin Quasem]

and each time the AIFUCTA was given different periods by which the Government would come out with the revised scheme. This vacillating attitude on the part of the Government of India in honouring its own commitment has, I apprehend, started creating unnecessary misgivings in the minds of the teachers and as a mark of protest against this inordinate delay on the part of the Government of India to announce necessary modifications in the scheme of revision of pay and conditions of service for the teachers, the members of the National Executive of the All India Federation of University and College Teachers' organisations participated in a "court arrest" programme in front of Shastri Bhavan, the official headquarters of the Ministry of Human Resource Development only on the 2nd of this month. I would strongly urge upon the Government of India to issue necessary Government orders in this regard immediately so that the college and university teachers all over India may enjoy the benefits of revised pay scales which are long overdue to them. Thank you.

Rise in prices of Yarn adversely affecting Handloom and Powerloom weavers

श्री मोहम्मद अमीन अंसारी (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, किसानी और काश्तकारी के बाद कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है जिसमें दो करोड़ से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर दिलाना चाहता हूं जहां एक ओर अनेक बुनकर फाकाकशी पर मुब्तला हो गए हैं, और दूसरी ओर उनको कोई काम नहीं मिल रहा है।

श्रीमन्, डेढ़ साल पहले सूत का दाम बढ़ना शुरू हुआ जब कि भारत सरकार की तरफ से सूत और कपास का ऐक्सपोर्ट करने का फैसला हुआ। सेठ साहूकारों व दलालों ने केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों पर दबाव डालकर यह साजिश की कि सूत और कपास एक्सपोट हो ताकि हमारे यहां दूसरा माल (सूत) आए और हम रातोंरात लखपति और करोड़पति हो जाएं। मान्यवर, डेढ़ साल में सूत का दाम 30 से 80 फीसदी तक बढ़ा। मैं अपने प्रान्त उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में सवा छ. लाख हाथकरघे हैं, हैंडलूम हैं और 90 हजार पावरलूम हैं। आज वहां सूत के भाव बढ़ाने से लोग फांका कर रहे हैं। मजदूरी के लिए जाते हैं तो उनको मजदूरी नहीं मिलती है। जिनकी दस्ताकारी और फनकारी की दुनियां के अन्दर धाक थी आज वे फनकार मिट्टी खोदते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाने के लिए मजबूर हैं। आज उनको बेराजगारी खाए जा रही है। मान्यवर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश के लगभग 40 लाख लोगों की रोजी रोटी का आज सवाल पैदा हो गया है। यहां की टैक्सटाइल मिनिस्ट्री इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मंत्री जी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हैं कि बुनकरों को राहत मिले लेकिन जो उनके हैंडलूम से मुताल्लिक अधिकारी हैं, और एन० टी० सी० के अधिकारी हैं, वह कुछ नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर जो एन० टी० सी० सरकार के अधीन हैं वह सेठों और साहूकारों व दलालों से साजिश व मिलकर कर कम दाम में सूत बेच रही है। पहले जब सूत का दाम बढ़ाने का इरादा करते हैं तो एजन्टों को बुलाकर उनके पास दस हजार बेल्स की गुंजाइश है तो दस हजार गांठों का वह सौदा कम दाम पर तय कर लेते हैं। उसके बाद दस दिन के अंदर फिर सेल की कमेटी बैठती है और थोड़ा सा माल (सूत) ऊंचे दामों पर बेच देते हैं और महाजन, सेठ, साहूकार सूत का भाव बढ़ाकर बेचते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं होती है और जिस दिन से एन० टी० सी० व उ० प्र० की सरकारी व सहकारी कताई मिलें भाव बढ़ाती है है उसी दिन से व्यापारी वह माल (सूत) बेचने लगते हैं।

(समय की घंटी)

महोदय, मैं पहली मर्तबा बोल रहा हूं। मुझे दो मिनट और समय दीजिए। मैं वहां की हालत जानता हूं। सरकारी अधिकारी लोग सेठ, साहूकारों के हाथ खेल रहे हैं और गरीब बुनकर ो मरना पड़ रहा है। इसीलिए केन्द्रीय सरकार से मेरी मांग हैं कि वह एन० टी० सी० ा,र उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव डाले कि उनकी जो भी मिलें हैं वे बुनकरों को सस्ता सूत नो प्राफिट नो लास बेसिस पर दिये जायें। बुनकरों को कुछ सबसिडि देकर सस्ता सूत, सस्ते दामों से उनको हैंडलूम कारपोरेशन और यू० पी० के जो डिपो हैं उनसे सस्ता सूत उपलब्ध करवाएं। एन० टी० सी० की मिलें कहते हैं घाटे में जा रही हैं। मैं केन्द्र सरकार से दावा करता हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश में दो एन० टी० सी० की मिलें दे दें मैं प्राफिट में दिखा दूंगा और 10–20 रु. सस्ता सूत पर बंडल में बुनकरों को दिला सकता हूं, यह मेरी जिम्मेवारी है।

मान्यवर, हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी गरीब लोगों को कपड़ा सस्ता उपलब्ध हो इसलिए जनता कंट्रोल क्लाथ धोती की उन्होंने स्कीम बनाई और बहुत अच्छी वह चली और वर्तमान हमारे प्रधान मंत्री भी इसको चला रहे हैं। मगर मुझे खेद है मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह मांग करता हूं कि वह तो जनता धोती कंट्रोल क्लाथ है, गरीब लोगों, देहात में रहने वालों, किसानों और मेहनतकश लोगों को वह जनता धोती नहीं मिल रही है। वह जनता धोती उत्तर प्रदेश में हैंडलूम कारपोरेशन व यू० पी० क० के जरिए वह सारा का सारा जनता धोती क्लाथ, वह कपड़ा एक गांठ (100 जोड़) एक गांठ (1000) के हिसाब से ब्लैक में साहूकारों दलालों के हाथ बेचा जा रहा है, जो जुर्म है। उसकी छपाई मथुरा, कानपुर, फर्रुखाबाद उलाव और दूसरी जगहों पर हो रही है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार सबसिडि इस पर देती है, उसकी सी० बी० आई० के जरिए जांच करवाएं और कहीं अगर छापा मारा जाए तो करोड़ों रु. का यह कंट्रोल क्लाथ धोती मथुरा के गोदामों में, ट्रांसपोर्ट के गोदामों में, सेठ-साहूकारों के घरों में वह मिलेगा। मान्यवर, हथकरघा निगम उ० प्र० व यू० पी० क० धोखाधड़ी कर रहे है और केन्द्रीय सरकार इन्हें अनुदान देती है, सबसिडि देती है, सब कुछ देती है इसलिए केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कड़ाई के साथ उसे देखे और मान्यवर, बहुत जल्दी में बहुत कुछ रोके जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप पहले मुझे कम से आधे घंटे का समय देंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : एक मिनट बैठिए।

For the benefit of the new Members, I want to tell that Special Mentions are allowed only for three minutes. I request the new Members not to take their maiden opportunity in the Special Mentions. Then they will have to abide by the three-minute rule.

श्री मोहम्मद अमीन अन्सारी : मान्यवर मेरा सिल्क का मामला रह गया है।

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Mohammed Amin Ansari did not know this rule. I am allowing him. I am requesting the other new Members not to take their maiden opportunity in the Special Mentions. Then they will have to abide by the 3-minute rule.

श्री मोहम्मद अमीन अंसारी : मान्यवर, आप जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश व हिन्दुस्तान के अन्दर सिल्क का भाव चार सौ रु० किलो से बढ़कर हमारे उत्तर प्रदेश में बनारस, मुबारकपुर, खैराबाद में 11 सौ रु० किलो हो गया था। हम डेढ़ साल से मांग करते चले आ रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार, टैक्सटाइल मिनिस्ट्री, वह रेशम चाइना या कोरिया, जहां से भी हो सके, जहां से पहले इम्पोर्ट करती थी इम्पोर्ट करके बुनकरों

[श्री मोहम्मद अमीन अन्सारी]

को छः सौ रु. किलो पर सिल्क उपलब्ध कराए। मुझे खेद है कि छः महीने पहले टैक्सटाइल मिनिस्टर साहब ने बनारस में यह एलान किया था कि हम सिल्क इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। हम दिन गिनते गए, हम घड़ियां गिनते गए मगर सिल्क का पता नहीं चला। छः महीने के बाद अब सिल्क आया जब सेठ-साहूकार पूरी तरह से बुनकरों का शोषण कर चुके थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि वह रेशम जो 715 रु. किलो बिक रहा है, उसका दाम ज्यादा है। मान्यवर, वह छः सौ रू. किलो बिकवाया जाए, चाहे केन्द्र सरकार सबसिडि दे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): मैं इनके विचारों का समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Malaviya, you are a senior Member. If you wanted, you could have sought the permission of the Chair. परमिशन तो लेनी ही चाहिए। बिना परमिशन आप जो बोलेंगे वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री मोहम्मद अमीन अन्सारी जी ने जो मुद्दा उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के जो बुनकर हैं, बहुत ही समस्याग्रस्त हैं। मैं भी आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो समस्याएं उन्होंने उठाई उन पर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। लाखों-लाख बुनकर दिल्ली में भी आकर प्रदर्शन कर चुके, बनारस में भी गिरफ्तारियां दीं, जामनगर में भी गिरफ्तारियां दीं। सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना होगा जिससे गरीबों की रोटी रोजी चले।

ought conditions in certain parts of Uttar Pradesh

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से बहुत आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व विषय पर उल्लेख करने का आपने इस माननीय सदन में अवसर दिया।

मान्यवर, गतवर्ष इन शताब्दी का सबसे बड़ा और भयंकर सूखा पड़ा जिसके कारण उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण देश का अधिकांश भाग बुरी तरह से प्रभावित हुआ।

उत्तर प्रदेश में सूखा राहत के नाम पर जो भी धन दिया गया उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। किसान को इसका कोई लाभ नहीं मिल सका। फिर भी किसान ने किसी प्रकार रबी की बोआई की और जब रबी की फसल लगभग तैयार हो गयी उसी समय उत्तर प्रदेश के लगभग दो तिहाई जिलों में उपलवृष्टि और तूफान के कारण फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गयीं। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले प्रभावित हुए। बाराबंकी जिले में तो न केवल फसल की बर्बादी हुई बल्कि कई व्यक्ति ओलावृष्टि से मर भी गये। राज्य सरकार ने इस सबंध में जो भी राहत कार्य किया है वह नगण्य और मजाक है। तथा राजस्व व अन्य देय की वसूली किसानों से उत्पीड़नात्मक माध्यम से की जा रही है।

हरियाणा प्रदेश में जहां भी इस प्रकार से किसान देवी आपदा, ओलावृष्टि तूफान और आग लगने से तबाह हुआ है वहां हरियाणा की लोकप्रिय सरकार मुख्य मंत्री माननीय देवी लाल जी ने तुरन्त मौके पर पहुंच कर अथवा अधिकारियों को भेजकर इस प्रकार की आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को चार सौ रुपए प्रति एकड़ की दर से क्षतिपूर्ति किया है

अतः लोक महत्व एवं जनहित के इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं यह मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में ओला वृष्टि तथा तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराकर ऐसी आपदा से